केजुग्रल लेबरर्स के बारे में भी हमें दर्द है। केजुग्रल लेबरर ग्रौर टेम्प्रेरी लेबरर जो कि 5–20 साल से चले ग्रा रहे हैं उनको भी प्रोटेक्शन देने के बारे में हम कुछ करने वाले हैं। कांट्रेक्ट लेबरर सिस्टम को भी हम ग्रबालिश करने की सोच रहे हैं। हिन्दुस्तान का जो मजदूर है उसको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन देने के लिए हम सोच रहे हैं। इस सोचने में ग्राप वायलेंस की बात कहां से ले ग्राये? पूरी कांफ्रेंस की बात को ग्रापने देखा होगा ग्रौर उसको देखते हुए वायलेंस की बात करना ठीक नहीं है।

कांफ्रेंस में जो डिसीजन ले लिये गये हैं, लेबर मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिये हैं उन डिसीजनों पर कानून पार्लियामेंट में बहुत जल्दी ग्राने वाला है। ऐसा तो नहीं कि प्रिन्टिंग प्रेस में दे कर ही यहां कानून ग्रा जाएगा। कानून जो बनाता है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंटस से भी हमें बात करनी है। स्टेट गवर्नमेंटस से हम बातचीत कर रहे हैं ग्रौर तमाम चीजों की हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राप हमारी मदद करने के बजाय, हमारी सपोर्ट करने के बजाय वायलेंस के बारे में बात करते हैं। ग्रगर बोम्बे में वायलेंस होगा तो ग्राप भी वहां से भाग जाएंगे, ग्रापकी यूनियन भी वहां से भागने वाली है। फिर ग्राप सेन्टर से कहेंगे कि हमें शेल्टर दो। इस तरह से ग्रापने जो बात छेड़ी है वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप में मजदूरों के लिए हमारे कदम ग्रागे बढ़ेंगे ग्रौर उन्हीं कदमों के ग्रन्तर्गत हम लेबरलाज में काफी तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : ...... के बारे में ग्रापने कुछ नहीं कहा।

श्री टी० ग्रंजय्या : किसी भी चीज के बारे में ग्रापके बोलने की जरूरत नहीं होगी। वह भी हम कर रहे हैं, उसका भी हमें पता है।

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SIXTH REPORT

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara): Sir, I beg to present the Sixth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

FIRST REPORT

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Sir, I beg to present the First Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.39 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) NEED FOR PREFERENCE IN EMPLOYMENT TO LOCAL PERSONS IN MATHURA OIL REFINERY.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के ग्रधीन सूचना देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि तेल शोधक कारखाने मथुरा (उ० प्र०) के ग्रधिकारियों की कार्यप्रणाली पर जनता में गहरा ग्रसन्तोष है। वहां की जनता को शिकायत है कि जब तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी तो मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ग्रौर माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मथुरा में बृहत् सभा में घोषणा की थी कि इस कारखाने से देश का हित होगा ही, मथुरा ग्रौर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी काम मिलेगा, बेकारी दूर होगी। जिनकी भूमि जा रही है उनको काम देने में प्राथमिकता दी जायेगी।

ग्रब जनता की शिकायत है कि नौकरी ग्रौर ठेका ग्रधिकतर बाहर के ग्रादमियों को ही मिल रहे हैं। मथुरा नगरी में बाहर के लोग ग्राकर बसने लगे हैं जिनकी भूमि गई उनको नौकरियों में प्राथमिकता नहीं दी गई ग्रौर मथुरा जिले ग्रौर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी प्राथमिकता नहीं दी गई। कारखाने के ग्रधिकारी जो ग्रधिकतर ग्रन्य प्रदेशों के हैं वे ग्रपने क्षेत्र के ग्रादमियों को ही प्राथमिकता देते हैं। इसलिए जनता ग्रान्दोलन कर रही है। ग्रनेक बार लोगों ने ग्रामरण ग्रनशन किए हैं। लिखकर मंत्री जी से शिकायत की है। ग्रब जनता में गहरा ग्रसन्तोष है ग्रौर सत्याग्रह की सम्भावना है। वहां जो सामान कारखाने में प्रयोग हो रहा है उसके सम्बन्ध में ग्राम धारणा है कि घटिया किस्म का है। नौकरियों के सम्बन्ध में ग्राम धारणा है कि उनका नीलाम होता है।

माननीय मंत्री जी वहां जाते हैं तो वहां के संसद् सदस्य तक को पता नहीं लगता। यदि इस ग्रोर सरकार शीघ्र ध्यान नहीं देगी तो वहां बहुत बड़े पैमाने पर ग्रान्दोलन होने की सम्भावना है ग्रौर कारखाने की प्रगति में बाधा पड़ेगी।

[श्री दिगम्बर सिंह]

जनता कहती है कि भूमि मथुरा की गई, मथुरा जिले की जनता को हानि होगी, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, यमुना का पानी गन्दा होगा । गहरे ट्यूबवैल कारखाने के वास्ते नीचे से पानी निकालेंगे । उससे मथुरा के किसानों के नलकूपो के लिए पानी नही रहेगा । ताजमहल को हानि पहुंचेगी । भरतपुर में देश का सब से महत्वपूर्ण पक्षी बिहार (घना) में पक्षी नही आएगे । अनेक बाहर के लोग मथुरा मे आकर बस जायेग । हानि होगी मथुरा और मथुरा के आसपास की जनता की और लाभ उठायेंगे बाहर के लोग । पैट्रोलियम मत्रालय के माननीय मत्री जी से मेरा निवेदन है कि अविलम्ब उचित कारंवा ई करे और जनता मे विश्वास पैदा करे ताकि अधिक असन्तोष न फैले । कृष्ण भगवान की पवित्र भूमि में जो लोग देश और विदेश से आते है, उनका स्वागत होता है । किन्तु इस असन्तोष के कारण ऐसा न हो कि जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने कम के खिलाफ आन्दोलन किया था, ब्रजवासियो को भी उसी प्रकार इस असन्तोष के कारण वैसा ही आन्दोलन करना पडे ।

(ii) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF FOODGRAINS TO UTTAR PRADESH FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAMME

श्री जैनल बशर (गाजीपुर) मै नियम 377 के अधीन लोक महत्व के एक श्न को उठाना चाहता हू और आशा करता हू कि कृषि मत्री जी इस सम्बन्ध मे एक वकतव्य देगे ।

इस समय पर्याप्त मात्रा मे खाद्यान्न न पहुचाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद और झासी मडलो मे काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चलाए ज रहे सभी कार्य ठप्प हो गए है । वैसे तो उत्तर प्रदेश मे खाद्यान्न के मामले मे माग और आपूर्ति मे बराबर अन्तर रहा है परन्तु इस ममय यदि अन्तर बाकी रखा गया तो आने वाले महीनो के लिए उत्तर प्रदेश मे भयकर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । इस जुलाई के महीने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 97 खाद्यान्न स्पेशलो की माग की है । इसके विपरीत भारत सरकार ने 64 स्पेशल भेजना मजूर किया है और जिम रफ्तार से स्पेशल भेजे जा रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि इतना भी पहुच पाना मुश्किल है ।

ऐसी स्थिति मे मै केन्द्रीय कृषि मत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश और विशेष कर वाराणसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजावाद और झासी मंडलो मे उत्तर प्रदेश सरकार की माग के अनुसार शीघ्रतिशीघ्र खाद्यान्न पहुचाने की व्यवस्था करे । यदि जरा भी विलम्ब किया गया तो भयकर अकाल से पीडित यहा के लोग भुखमरी के कगार पर खडे हो जायेगे ?

(iii) NEED FOR LEGISLATION TO TAKE OVER AUROVILLE AS A NATIONAL MEMORIAL OF SHRI AUROBINDO.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Under Rule 377, I wish to raise the following matter of public importance:

Several years ago a remarkable project entitled Auroville was started by the Mother of Sri Aurobindo Ashrama of Pondicherry. It was envisaged as a new type of spiritual community where the entire life and activity would revolve around the integral spiritual quest. It included a number of very interesting experimental activities in the field of agriculture, education and community living. As long as the Mother was alive the project continued to grow, but after her death the whole concept has unfortunately become distorted. Endless conflicts have been raging between the Sri Aurobindo Society, which claims exclusive ownership of this vast project, and the 'Aurovillians' who are living there. Unsavoury incidents of violence have also occurred, and there have been grave charges levelled by the two parties against each other. Recently there was again a clash over the Matri Mandir which is supposed to be the spiritual centre of Auroville.

A vast project like Auroville involves extensive acquisition of land in the State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pondicherry; numerous visa and passport problems connected with the many foreigners who are living in Auroville, and extensive developmental and administive dimensions. Clearly all these are far beyond the capacity of the Sri Aurobindo Society to manage, particularly as the President of this Society has himself been accused of numerous misdemeanours.

It is a tragedy that a magnificient concept like Auroville, which has received recognition from UNESCO

should have become bogged down in petty intrigues and administrative bungling. I would urge that the Government of India should immediately move to take over Aurobille as a national memorial of Sri Aurobindo and for this purpose bring a Bill before the Parliament as early as possible.

(iv) SUPPLY OF ESSENTIAL COMMODITIES AT REASONABLE PRICES.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। चीनी, दाल, तेल, साबुन एवं अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में पुन: वृद्धि हो गयी है। चीनी का दाम कहीं-कहीं तो आठ रूपए प्रति किलो हो गया है, जिससे गरीब आदमी तो उसे खरीद भी नही सकता। गुड़ की भी कीमत एक माह के भीतर दुगुनी हो गयी है। बेबी-फड की कीमत प्राय: बढ़ती चली जा रही है। सरकार की वर्तमान आर्थिक नीति में निहित दोष के कारण बढ़ती हुई कीमतों पर नियंत्रण नही स्थापित हो पा रहा है। बहुत सी वस्तुयें जसे सीमेंट आदि तो उपभोक्ताओ को मिल भी नही पा रही है।

अत: सरकार को शीघ्र प्रभावशाली कदम उठाने चाहियें जिससे उपभोक्ता वस्तुये सस्ते दामों पर आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें। बजट पेश होने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि अत्यन्त चिन्ताजनक है। नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को तत्काल इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए।

(v) NEED TO RESUME RELIEF WORK IN THE TRIBAL AREAS OF JHABUA RATALM, DHAR AND KHARGON DISTRICTS MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में झाबुआ रतलाम, धार, खरगोन जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में जहां एक और अकाल राहत कार्य बन्द कर दिए गए हैं, वहां दूसरी ओर कई महीनों की मजदूरी का भुगतान उन्हें नहीं किया गया है। साथ ही सस्ते अनाज की दुकानों में आदिवासियों का मुख्य भोजन मोटा अनाज, ज्वार, मक्का आदि उपलब्ध नही हैं। बाजार में ऊंचे दामों में अनाज मिल रहा है, जिसे आदिवासी क्रय नहीं कर सकता है।

अत: सर्वत्र आदिवासियों में भुखमरी एवं असन्तोष व्याप्त है। राज्य सरकार को निर्देश दये जाये कि जब तक नई फसल नहीं पके तब तक राहत कार्य जारी रखे जायें एवं मजदूरी का अविलम्ब भुगतान किया जाये और शासकीय सस्ते अनाज की दुकानों पर मोटे अनाज की व्यवस्था की जाये।

(vi) NEED FOR IMMEDIATE SUPPLY OF WHEAT FOR "FOOD FOR WORK" PROGRAME IN RAJASTHAN.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जो उनके गोदामों में जमा कर रखा था, उक्त स्टाक प्रान्त में दस दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया है। जिसके कारण राजस्थान प्रान्त में जिला बाडमेर, जैसलमेर, आदि में अकाल राहत कार्य चलते थे, वह बन्द हो गए हैं। अन्य कार्य जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे थे वे सभी बन्द हो गए हैं सस्ते अनाज की दुकानों में प्रान्त भर में गेहूं के न मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भयंकर असन्तोष है। गेहूं के भाव चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। अकाल राहत कार्य एवं अनाज के बदले कार्य, फूड फार वर्क नहीं चलने से कुछ जिलों में भुखमरी की स्थिति आ रही है। अत: केन्द्र सरकार तुरन्त राजस्थान प्रान्त में गेहूं का स्टाक जल्दी से जल्दी पहुंचा कर राजस्थान की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करे।

(vii) REPORTED VIOLATION OF THE COMPANIES ACT, INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT, ETC., BY FOREIGN COMPANIES OPERATING IN INDIA.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it has been reported that official inspection has brought out that branches and subsidiaries of Foreign Companies operating in India are violating with impunity the Companies Act, Industrial Development Regulation Act (Licencing), Foreign Exchange Regulation Act and MRTP.

The British companies numbering 319 some time ago were on top of the list in this adventure. Although the number has come down because of FERA compulsion, they have increased the remittances considerably. Their assets are going up by leaps and bounds. In 1973-74, the white money value of their assets was

[Shri Joytirmoy Bosu]

shown as Rs. 1790.4 crores, by 1978-79 it has gone up to Rs. 2401.4 crores. In 1975-76, it was Rs. 2178.2 crores. Besides, there is a huge amount of black money mainly kept with their distributors, agents dealers and benamidars. It is estimated that an amount of Rs. 1500 crores go out of the country through invoice manipulation every year. A big part of this money is given in Indian rupees to the foreign agents and missionaries for anti-India activities in the country.

The Managing Director of a Motor Company, a Britisher who has shifted his activities from Calcutta to Shillong, has given millions of rupees to foreign missionaries in Indian rupees and took back the same in foreign currencies, abroad with a premium.

Detailed reply from the concerned Ministry is called for.

12.52 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL, 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF INDUSTRY—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Industry.

Mrs. Krishna Sahi.

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, कल इस सदन में जब माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीज, भाषण दे रहे थ, तो मैं ने बहुत ध्यान से उसको भी सुना और तीन वर्ष का उनका और उनकी पार्टी का परफामेंन्स भी देखा । वह अपने भाषण में अपनी सरकार की नीतियों की दुदुंभि भी जोर से बजा रहे थे और अपनी उपलब्धियों की झड़ी भी लगा रहे थे । लेकिन मैं समझती हूं कि उस श्रृंखला में वह कुछ कड़ियों को जोड़ना भूल गये । मैं अपनी ओर से उनकी तथा-कथित सफलताओं को उसमें जोड़ना चाहती हूं ।

मैं जानना चाहती हूं कि जनता पार्टी के शासन-काल के तीन वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में कितनी हड़तालें हुई, कितने लाक-आउट्स हुए, हमारे कितने उद्योग-धंधे बन्द हो गये और कितने मैनडेज का लास हुआ । इसके अलावा हमारे औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन कहां तक पहुंच गया ? गत वर्ष हमारा उत्पादन शून्य तक पहुच गया, उससे हमारी कितनी राष्ट्रीय क्षति हुई ? ये सारी बाते हमारे सामने प्रश्न-चिन्ह बन कर उपस्थित हैं ।

जनता पार्टी की सरकार तीन वर्षों तक रही और अपने औद्योगिक साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने बड़े बड़े उद्योगपतियों पर से सभी प्रकार के नियंत्रणों को हटा लिया । मनोपलीज कमीशन की भूमिका नगण्य रह गई और उसके अधिकार बहुत सीमित हो गए । बड़े बड़े वित्तीय संस्थानों और बडे बडे उद्योगपतियों को सूद की रियायत मिल गई और उनको साधन आसानी से उपलब्ध किये गये । कहने का मतलब यह है कि जहा उनके अपने खजाने मोटे हो गये, वहां औद्योगिक क्षमता निम्नतम स्तर पर पहुच गई ।

देश को आर्थिक स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाना प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था । उनका दर्शन देश मे औद्योगिक क्रान्ति का अग्रदूत बन कर आया था । जब तक हमारी पार्टी की सरकार रही, तब हम आत्म-निर्भरता की ओर जा रहे थे । लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया, तो इस दर्शन पर कड़ा प्रहार हुआ और इसका सब से बुरा असर औद्योगिक क्षेत्र पर पड़ा । मैं उसका एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहती हूं । तीन वर्षों में रांची के एच ई सी को खोखला बना दिया गया । पता नहीं किस को व्यवस्थापक के रूप में इन्होने भेजा, मैं किसी का नाम नही लेना चाहती, लेकिन जो व्यवस्थापक यहां से गए उन्होने तीन वर्षों में उस को खोखला ही नही बना दिया बल्कि सब तरफ से उस को अपंग बना कर छोड दिया । 77, 78 और 79 तक 65 करोड़ का तो कारखाने का लास हुआ है और इस के अलावा जो उस के एस्टैब्लिशमेंट पर खर्च था वह तो बढ़ता ही चला गया । इसी एच ई सी में 76 और 77 में इस के उत्पादन के अंदर अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी और मुनाफा भी हुआ था । एच ई सी हिन्दुस्तान की आर्थिक ऊंचाई का एक बहुत बड़ा स्तम्भ है । लेकिन वहां ऐसे व्यवस्थापक गए जो उस की निगरानी तो कुछ कर नहीं सके, उस का उत्पादन कुछ कर नहीं सके उलटे वहां जो उत्पादन हो सकता था और होता था उस को भी बन्द कर दिया । तत्कालीन उद्योग मंत्री ने संभवत: जैसी कि हम लोगों की जानकारी है, वैस्ट जर्मनी की एक

---

*Moved with the recommendation of the President.